लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4974

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

परिधान 2030 विजन

4974. थिरु दयानिधि मारन:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परिधान 2030 विजन में तमिलनाडु राज्य की विशिष्ट भूमिका क्या है क्योंकि तमिलनाडु एक प्रमुख वस्त्र केन्द्र है जो भारत के वस्त्र निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है;

(ख) 350 बिलियन डॉलर के वस्त्र उद्योग और 100 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य में तमिलनाडु द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा;

(ग) विगत दस वर्षों के दौरान तमिलनाडु में वस्त्र अवसंरचना के लिए किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उनका उन्नयन करने के लिए तमिलनाडु में मौजूदा टेक्सटाइल पार्कों को क्या सहायता दी जा रही है;

(घ) विगत 10 वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितने वस्त्र कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ङ) तमिलनाडु स्थित वस्त्र उद्योगों को वहनीय पद्धतियों को अपनाने और सर्कुलर वस्त्रों के परिवर्तन को स्वीकारने के लिए क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(च) राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु को ऑटोमोटिव और मेडिकल टेक्सटाइल जैसे तकनीकी वस्त्रों में अपनी उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से निधियां आवंटित की गई हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (च): सरकार, वस्त्र 2030 विजन को प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीक और उच्च विकास वाले उत्पाद क्षेत्रों पर फोकस कर रही है, अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठा रही है, बड़े पैमाने पर प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, सस्टेनेबिलिटि को केंद्र में रख रही है, साथ ही बड़े पैमाने पर आजीविका के अवसर सुनिश्चित कर रही है, पारंपरिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और तमिलनाडु सहित देश भर में विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू करके कच्ची सामग्री की मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर बन रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना है जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना का निर्माण करना है; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मेन मेड फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को एंड टू एंड सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना भी लागू कर रहा है। इन योजनाओं के तहत विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना के लिए तमिलनाडु (विरुद्धनगर) में एक साइट को अंतिम रूप दिया है। साथ ही, तमिलनाडु में एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना के तहत 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 76 छोटे हथकरघा क्लस्टर और 2 मेगा हथकरघा क्लस्टर को 94.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे 1,17,092 हथकरघा कामगारों को लाभ हुआ है। इसके अलावा, समर्थ के तहत तमिलनाडु राज्य में कुल 681 प्रशिक्षण केंद्र शुरु किए गए हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) अनुसंधान और विकास, व्यवसाय स्टार्टअप, कौशल विकास, निर्यात संवर्धन को सहायता प्रदान करता है, जिससे तमिलनाडु सहित पूरे भारत में विभिन्न तकनीकी वस्त्र समूहों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एनटीटीएम के तहत मेडिकल टेक्सटाइल और ऑटोमोटिव टेक्सटाइल सहित तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु राज्य में 14.5 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ मेडिकल टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स, जियो टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, इंदु टेक के क्षेत्र में 11 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और 88.9 लाख रुपये के बजट परिव्यय के साथ मेडिकल टेक्सटाइल्स क्षेत्र में 2 स्टार्टअप परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

***